

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 553]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2017 —आश्विन 21, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017

क्र. एफ ए-3-71-2017-1-पांच (126).—जहां कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017), एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है, के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहां तक की इसका संबंध उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से है;

अतः, अब, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, यथा

1. इस आदेश को मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 कहा जाएगा.

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,—

- (i) एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या सेवा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिनमें वे सेवाएं भी आती हैं जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजीसन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक कि इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों.

- (ii) आगे और भी यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजीसन स्कीम के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने में उसके सकल कारोबार की गणना करने में किसी छूट प्राप्त सेवा की आपूर्ति के मूल्य को, जिसमें वे सेवाएं भी आती हों जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं जहां तक इसके प्रतिफल की अभिव्यक्ति ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से हुआ हो, शामिल नहीं किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. एफ ए-3-71-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-71-2017-1-पांच (126), दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2017

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2017

No. F. A.-3-71-2017-1-V (126).—WHEREAS, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), hereinafter in this order referred to as the said Act, in so far as it relates to the provisions of Section 10 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 172 of the said Act, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following order namely :—

1. This Order may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017

2. For the removal of difficulties,—

- (i) it is hereby clarified that if a person supplies goods and/or services referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act and also supplies any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, the said person shall not be ineligible for the composition scheme under Section 10 subject to the fulfilment of all other conditions specified therein.
- (ii) it is further clarified that in computing his aggregate turnover in order to determine his eligibility for composition scheme, value of supply of any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.